



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 653]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 12, 2009/कार्तिक 21, 1931

No. 653]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 12, 2009/KARTIKA 21, 1931

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2009

सं.का.नि. 818(अ).— केन्द्रीय सरकार, जीवन बीमा अधिनियम, 1956 (1956 का 31) की धारा 48 की उपधारा (1) के साथ पठित उपधारा (2) के खंड (गग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय जीवन बीमा निगम के विकास अधिकारियों के कारबार निर्वहन से संबंधित सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का विनियमन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं** — इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) “अधिनियम” से जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अभिप्रेत है ;

(ख) “वार्षिक पारिश्रमिक” से अभिप्रेत है : मूल वेतन, विशेष वेतन, व्यक्तिगत वेतन, महंगाई भत्ते, तथा सभी भत्ते और लाभ-निरपेक्ष भागीदारी या अनुग्रह बोनस जो मूल्य निर्धारण वर्ष में विकास अधिकारी को देय या मिला है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यय भी है जो उस वर्ष के दौरान यात्रा, आवासीय, टेलीफोन, मोबाइल बीमा प्रीमियम तथा मोटर वाहन के संबंध में उसे निगम द्वारा देय है या जिसकी बाबत निगम ने उसकी प्रतिपूर्ति की है जो निगम ने उपगत किया है, किन्तु इसके अंतर्गत नियम 13 के अनुसार उसे संदत्त प्रेरणा बोनस नहीं है ;

(ग) “मूल्य निर्धारण तारीख” से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

(I) राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को या इसके पश्चात् नियुक्त विकास अधिकारी के संबंध में,

(अ) अपनी सेवाकाल के प्रथम वर्ष में उस मास का प्रथम दिन जो उस मास के बाद आता है जिसमें वह अपनी नियुक्ति की तारीख से बारह मास की सेवा पूरी करता है ; और

(आ) अपनी सेवाकाल के प्रत्येक पश्चातवर्ती वर्ष में उस मास का प्रथम दिन जिसमें वह पिछली मूल्य निर्धारण तारीख से बारह मास का सेवा काल पूरा करता है ;

(II) राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व नियुक्त विकास अधिकारी के संबंध में,

(अ) राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से अपनी सेवा के प्रथम वर्ष में उस मास के प्रथम दिन जिसमें वह उस तारीख से बारह मास की सेवा पूरी करता है जिसको उसकी अंतिम वार्षिक वेतन वृद्धि भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृद्धि) नियम, 1960 के नियम 56 के उपनियम (2) के अनुसार प्रोदभूत हुई थी (चाहे निर्मोचित की गई हो या नहीं), और

(आ) अपनी सेवाकाल के प्रत्येक पश्चात्तवर्ती वर्ष में उस मास का प्रथम दिन जिसमें वह पिछली मूल्य निर्धारण तारीख से बारह मास का सेवा काल पूरा करता है ;

(घ) “मूल्य निर्धारण वर्ष” से अभिप्रेत है, दो लगातार मूल्य निर्धारण तारीखों के बीच की अवधि और खंड (ग) का उपखंड (1) की मद (अ) के अनुसार अभिनिश्चित मूल्य निर्धारण तारीख से पहले पड़ने वाली बारह मास की अवधि, और खंड (ग) के उपखंड (2) की मद (अ) के अनुसार अभिनिश्चित मूल्य निर्धारण तारीख से पहले पड़ने वाली सेवा की बारह मास की प्रत्येक अवधि भी मूल्य निर्धारण वर्ष होगी ;

(ङ) “लागत अनुपात” से विकास अधिकारी के संबंध में वह अनुपात अभिप्रेत है जो किसी वर्ष में उसके वार्षिक पारिश्रमिक का उस वर्ष के पात्र आदेय प्रीमियम से है और ऐसे आदेय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया गया है ;

(च) “वेतन ह्रास” से एक या अधिक अवसरों पर वेतनमान में एक या अधिक प्रक्रमों द्वारा मूल वेतन में कमी अभिप्रेत है ;

(छ) “विकास अधिकारी” से विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त वर्ग 2 का निगम का पूर्णकालिक वेतनभोगी कर्मचारी अभिप्रेत है ;

(ज) “अवप्रेरणा” से अवप्रेरणा सारणी में यथा उपबंधित वेतनवृद्धि का न दिया जाना या वेतनह्रास अभिप्रेत है ;

(झ) “आदेय प्रीमियम” से अभिप्रेत है, विकास अधिकारी संगठन के अभिकर्ताओं द्वारा प्राप्त कारबार के संबंध में निगम द्वारा प्राप्त प्रथम वर्ष के प्रीमियम का वह अनुपात जो समय-समय पर निगम द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय और सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष में समायोजित किया जाए ।

(ट) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट व्यापार क्षेत्र में कार्यरत विकास अधिकारी के संबंध में मूल्य निर्धारण वर्ष के बारे में “व्यय सीमा” से (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्यय सीमासारणी कहा गया है) उस तालिका के स्तंभ (2) की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट उस वर्ष के आदेय प्रीमियम का प्रतिशत अभिप्रेत है और यह ऐसे विकास अधिकारियों को लागू होगा जिनकी पुष्टि राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व तारीख को निगम की सेवाओं में हो गई है :-

व्यय सीमा सारणी

यदि विकास अधिकारी व्यापार क्षेत्र में कार्यरत हैं	आदेय प्रीमियम का प्रतिशत
(1)	(2)
क	19 प्रतिशत
ख	20 प्रतिशत
ग	21 प्रतिशत
घ	22 प्रतिशत

परंतु ऐसे विकास अधिकारी की बाबत जिसकी पुष्टि राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख को या इसके पश्चात् सेवा में हुई है, लागू व्यय सीमा वह होगी जो नीचे सारणी में विनिर्दिष्ट है :

व्यय सीमा सारणी

यदि विकास अधिकारी व्यापार क्षेत्र में कार्यरत हैं	आदेय प्रीमियम का प्रतिशत		
	पुष्टि के पश्चात् प्रथम मूल्य निर्धारण वर्ष में	पुष्टि के पश्चात् दूसरे मूल्य निर्धारण वर्ष में	पुष्टि के पश्चात् तीसरे और पश्चातवर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में
(1)	(2)	(3)	(4)
क	22 प्रतिशत	21 प्रतिशत	19 प्रतिशत
ख	23 प्रतिशत	22 प्रतिशत	20 प्रतिशत
ग	24 प्रतिशत	23 प्रतिशत	21 प्रतिशत
घ	25 प्रतिशत	24 प्रतिशत	22 प्रतिशत

टिप्पण :

(1) किसी भी मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए किसी विकास अधिकारी की व्यय सीमा उस वर्ष के आदेय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त की जाती है। यदि किसी विकास अधिकारी का उस वर्ष का वार्षिक पारिश्रमिक व्यय सीमा से अधिक है तो यह कहा जाता है कि उसने व्यय सीमा पार कर दी है ; ऐसे आधिक्य या उस अनुपात को, जो उसके वार्षिक पारिश्रमिक का उस वर्ष के आदेय प्रीमियम से है, ऐसे आदेय प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है।

(2) ऐसे विकास अधिकारी की दशा में जिसकी पुष्टि राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पूर्व तारीख को निगम की सेवाओं में हुई है, उपरोक्त सारणी में विनिर्दिष्ट प्रतिशत समुचित संक्रमणकालीन रियायतों यदि कोई हों, द्वारा बढ़ाई जाएगी जैसा खंड (न) में परिभाषित है :

परंतु संक्रमणकालीन रियायतें उन विकास अधिकारियों को लागू नहीं होंगी जो नियम 4 के अधीन शासित हैं।

(ट) “व्यापार क्षेत्र” से विकास अधिकारी के संदर्भ में व्यापार क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें वह विकास अधिकारी के रूप में काम करने के लिए तैनात है और क्षेत्र को उसका व्यापार क्षेत्र कहा जाता है यदि -

(अ) वह किसी नगर या शहरी सीमा या कस्बे में काम कर रहा है जिसकी अभिनिश्चित जनसंख्या 10 लाख से अधिक है ;

(आ) वह किसी नगर या शहरी सीमा या कस्बे में काम कर रहा है जिसकी अभिनिश्चित जनसंख्या 6 लाख या उस से अधिक किन्तु 10 लाख से अधिक नहीं है ; और

(इ) वह किसी नगर या शहरी सीमा या कस्बे में काम कर रहा है जिसकी अभिनिश्चित जनसंख्या 6 लाख से अन्यून है ; और

(ई) वह स्पष्टीकरण (2) या स्पष्टीकरण (3) में विनिर्दिष्ट ग्रामीण क्षेत्र या अति ग्रामीण क्षेत्र या किसी पहाड़ी क्षेत्र में कार्य कर रहा है या किसी ऐसे अन्य पहाड़ी क्षेत्र में कार्य कर रहा है जिसे केन्द्रीय सरकार निगम के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे।

स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजन के लिए,-

- (1) “अभिनिश्चित जनसंख्या” से भारत सरकार की सबसे अंतिम जनगणना रिपोर्ट के आधार पर अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है ;
- (2) विकास अधिकारी को तब “ग्रामीण क्षेत्र” या “अति ग्रामीण क्षेत्र” में कार्यरत कहा जाता है यदि उसका मुख्यालय किसी ऐसे स्थान पर है जिसकी अभिनिश्चित जनसंख्या 50 हजार या उससे कम और उसके व्यापार क्षेत्र की अभिनिश्चित जनसंख्या डेढ़ लाख से अधिक नहीं है ;
- (3) विकास अधिकारी को तब “पहाड़ी क्षेत्र” में कार्यरत कहा जाता है यदि उसका मुख्यालय मीन समुद्री स्तर से 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई पर स्थित है ;
- (ठ) “पूर्ववर्ती वर्ष” या “सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष” से सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष अभिप्रेत है ;
- (ड) “वहित व्यय सीमा” या “विहित लागत अनुपात” से विनियम 4 के अनुसार अभिनिश्चित बढ़ाई गई व्यय सीमा अभिप्रेत है जहां ऐसी व्यय सीमा विकास अधिकारी पर लागू होती है या यदि वह उस पर इस प्रकार लागू नहीं होती वहां पद से वह व्यय सीमा अभिप्रेत होगी जो उसको लागू होती है ;
- (ढ) “सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख” से वह मूल्य निर्धारण तारीख अभिप्रेत है जो उस तारीख से ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष के लिए किसी विकास अधिकारी के कार्यपालन का इन नियमों के अधीन किसी प्रयोजन के लिए मूल्यांकन किया जाता है या कर्मचारिवृंद नियमों के अधीन इसका मूल्यांकन किया गया था ;
- (ण) “सेवा” से वह अवधि अभिप्रेत है जो विकास अधिकारी के रूप में कर्तव्य पूरा करते हुए तथा कर्मचारिवृंद नियमों के नियम 69 के उपनियम 4 के अधीन क्षमा की गई असाधारण छुट्टियों सहित छुट्टी पर बिताई गई है ;
- (त) “कर्मचारिवृंद नियम” से भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृंद) नियम, 1960 अभिप्रेत है ;
- (थ) “उत्तरवर्ती वर्ष” से सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से प्रारंभ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है ;
- (द) “अवप्रेरणा सारणी” से नियम 6 के उपनियम (1) में संलग्न सारणी अभिप्रेत है ;
- (ध) “बढ़ाई गई व्यय सीमा” से नियम 4 में यथावर्णित व्यय सीमा अभिप्रेत है ;
- (न) “संक्रमणकालीन रियायत” से ऐसे विकास अधिकारी को लागू नीचे सारणी में यथाविनिर्दिष्ट रियायत अभिप्रेत है जिसकी पुष्टि राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से पूर्व तारीख को निगम की सेवाओं में हुई है :

सारणी

भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 के नियम 2 के खंड (ठ) में यथापरिभाषित व्यापार क्षेत्र	क	ख	ग	घ	ङ
इस प्रकार निरसित भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 के नियम 2 के खंड (ट) में व्यय सीमा सारणी में यथाउपबंधित व्यय सीमा राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख पर आधारित पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संक्रमणकालीन रियायत का आधार लिया जाएगा और पश्चातवर्ती वर्षों का उल्लेख इस प्रकार है	22 प्रतिशत	23 प्रतिशत	24 प्रतिशत	25 प्रतिशत	26 प्रतिशत
क) प्रथम मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	21	22	23	24	25

	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत	प्रतिशत
ख) दूसरे मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	20 प्रतिशत	21 प्रतिशत	22 प्रतिशत	23 प्रतिशत	24 प्रतिशत
ग) तीसरे मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	19 प्रतिशत	20 प्रतिशत	21 प्रतिशत	22 प्रतिशत	22 प्रतिशत

(प) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं किन्तु कर्मचारिवृद्ध नियमों में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उनके उन कर्मचारिवृद्ध नियमों में हैं।

3. पदावधि - इन नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, विकास अधिकारी, उसी अवधि तक और उसी रीति में पद धारण करेगा जिसमें कि निगम के अन्य कर्मचारी धारण करते हैं :-

परंतु यह स्वयं को लागू व्यय सीमा का अनुपालन करेगा :

परंतु यह और कि किसी विकास अधिकारी की सेवाएं ऐसे अल्प कारबार उत्पादन के आधार पर, जिससे उसकी लागू व्यय सीमा से अधिक लागत अनुपात हुआ है, समाप्त नहीं की जाएंगी जब तक कि नियम 6 में यथा उपबंधित व्यय सीमा का अनुपालन करने का उसे अवसर प्रदान न किया गया हो।

4. विकास अधिकारियों को लागू व्यय सीमा - (1) विकास अधिकारी की लागू व्यय सीमा वह होगी जो नियम 2 के खंड (अ) में यथा उपबंधित व्यय सीमा सारणी में यथाविनिर्दिष्ट होगी और यह दो प्रतिशत बढ़ाकर उसके व्यापार क्षेत्र को लागू व्यय सीमा होगी यदि सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के ऐसे प्रारंभ पर या इसके पूर्व उसने 55 वर्ष की आयु पूरी कर ली है :

परंतु उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट बढ़ाई गई व्यय सीमा व्यापार क्षेत्र 'क', 'ख', 'ग' और 'घ' की बाबत राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् प्रारंभ होने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को लागू होगी।

(2) ऐसे विकास अधिकारी की बाबत जिसकी पुष्टि राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पूर्व तारीख को हुई है और जिन्होंने सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के प्रारंभ पर विकास अधिकारी के रूप में दस वर्ष से अधिक सेवा की है,-

(क) प्रथम, द्वितीय और तृतीय मूल्य निर्धारण वर्षों में लागू व्यय सीमा नीचे सारणी में यथाउपबंधित होगी यदि उसने सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के ऐसे प्रारंभ पर या इसके पूर्व 50 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और 52 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है :

सारणी

भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 के नियम 2 के खंड (ठ) में यथापरिभाषित व्यापार क्षेत्र	क	ख	ग	घ	ङ
इस प्रकार निरसित भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 के नियम 4 के खंड (1) में व्यय सीमा सारणी में यथाउपबंधित व्यय सीमा राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख पर आधारित पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संक्रमणकालीन रियायत का आधार लिया जाएगा और पश्चातवर्ती वर्षों का उल्लेख	23 प्रतिशत	24 प्रतिशत	25 प्रतिशत	26 प्रतिशत	27 प्रतिशत

इस प्रकार है					
क) प्रथम मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	22 प्रतिशत	23 प्रतिशत	24 प्रतिशत	25 प्रतिशत	26 प्रतिशत
ख) दूसरे मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	21 प्रतिशत	22 प्रतिशत	23 प्रतिशत	24 प्रतिशत	24 प्रतिशत
ग) तीसरे मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	19 प्रतिशत	20 प्रतिशत	21 प्रतिशत	22 प्रतिशत	22 प्रतिशत

(ख) प्रथम, द्वितीय और तृतीय मूल्य निर्धारण वर्षों में लागू व्यय सीमा नीचे सारणी में यथाउपबंधित होगी यदि उसने सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के ऐसे प्रारंभ पर या इसके पूर्व 52 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और 53 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है :

सारणी

भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 के नियम 2 के खंड (ठ) में यथापरिभाषित व्यापार क्षेत्र	क	ख	ग	घ	ङ
इस प्रकार निरसित भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 के नियम 4 के खंड (1) में व्यय सीमा सारणी में यथाउपबंधित व्यय सीमा राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख पर आधारित पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संक्रमणकालीन रियायत का आधार लिया जाएगा और पश्चातवर्ती वर्षों का उल्लेख इस प्रकार है	24 प्रतिशत	25 प्रतिशत	26 प्रतिशत	27 प्रतिशत	28 प्रतिशत
क) प्रथम मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	23 प्रतिशत	24 प्रतिशत	25 प्रतिशत	26 प्रतिशत	27 प्रतिशत
ख) दूसरे मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	21 प्रतिशत	22 प्रतिशत	23 प्रतिशत	24 प्रतिशत	25 प्रतिशत
ग) तीसरे मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	19 प्रतिशत	20 प्रतिशत	21 प्रतिशत	22 प्रतिशत	22 प्रतिशत

(ग) प्रथम, द्वितीय और तृतीय मूल्य निर्धारण वर्षों में लागू व्यय सीमा नीचे सारणी में यथाउपबंधित होगी यदि उसने सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के ऐसे प्रारंभ पर या इसके पूर्व 53 वर्ष की आयु पूरी कर ली है और 54 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है :

सारणी

भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989	क	ख	ग	घ	ङ
--	---	---	---	---	---

के नियम 2 के खंड (ठ) में यथापरिभाषित व्यापार क्षेत्र					
इस प्रकार निरसित भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 के नियम 4 के खंड (1) में व्यय सीमा सारणी में यथाउपबंधित व्यय सीमा राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख पर आधारित पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संक्रमणकालीन रियायत का आधार लिया जाएगा और पश्चातवर्ती वर्षों का उल्लेख इस प्रकार है	24 प्रतिशत	25 प्रतिशत	26 प्रतिशत	27 प्रतिशत	28 प्रतिशत
क) प्रथम मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	23 प्रतिशत	24 प्रतिशत	25 प्रतिशत	26 प्रतिशत	27 प्रतिशत
ख) दूसरे मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	22 प्रतिशत	23 प्रतिशत	24 प्रतिशत	25 प्रतिशत	26 प्रतिशत
ग) तीसरे मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	21 प्रतिशत	22 प्रतिशत	23 प्रतिशत	24 प्रतिशत	24 प्रतिशत

(घ) प्रथम, द्वितीय और तृतीय मूल्य निर्धारण वर्षों में लागू व्यय सीमा नीचे सारणी में यथाउपबंधित होगी यदि उसने सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष के ऐसे प्रारंभ पर या इसके पूर्व 54 वर्ष की आयु पूरी कर ली है :

सारणी

भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 के नियम 2 के खंड (ठ) में यथापरिभाषित व्यापार क्षेत्र	क	ख	ग	घ	ङ
इस प्रकार निरसित भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 के नियम 4 के खंड (1) में व्यय सीमा सारणी में यथाउपबंधित व्यय सीमा राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख पर आधारित पश्चातवर्ती वर्षों के लिए संक्रमणकालीन रियायत का आधार लिया जाएगा और पश्चातवर्ती वर्षों का उल्लेख इस प्रकार है	25 प्रतिशत	26 प्रतिशत	27 प्रतिशत	28 प्रतिशत	29 प्रतिशत
क) प्रथम मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	24 प्रतिशत	25 प्रतिशत	26 प्रतिशत	27 प्रतिशत	28 प्रतिशत
ख) दूसरे मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	22 प्रतिशत	23 प्रतिशत	24 प्रतिशत	25 प्रतिशत	26 प्रतिशत
ग) तीसरे मूल्य निर्धारण वर्ष में लागू व्यय सीमा	21 प्रतिशत	22 प्रतिशत	23 प्रतिशत	24 प्रतिशत	24 प्रतिशत

(3) नियम 4 के उपनियम (1) और (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियम 6 के उपनियम (1) में यथाउपबंधित अवप्रेरणा सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता या नियम 6 के उपनियम (8) और (9) में विनिर्दिष्ट प्रतिशतता नहीं बढ़ाई जाएगी।

5. वेतनवृद्धि - (1) किसी विकास अधिकारी द्वारा वेतनवृद्धियां साधारणतया कर्मचारिवृद्धि नियमों के नियम 56 के अनुसार सामान्य क्रम में प्राप्त की जाएंगी जब तक कि वह अधिकतम ग्रेड में नहीं पहुंच गया हो या वेतनवृद्धि नियम 6 के अनुसार अनुज्ञात नहीं की जा सकती हों या कर्मचारिवृद्धि नियम के नियम 39 के अधीन अनुशासनात्मक अध्युपाय के रूप में नहीं रोकी जा सकती है।

(2) जहां किसी वर्ष में किसी विकास अधिकारी को कोई वेतनवृद्धि अवप्रेरणा के रूप में नियम 6 के अनुसार नहीं दी जाती है वहां ऐसी वेतनवृद्धि नियम 8 में अंतर्विष्ट उपबंधों के सिवाय किसी पश्चातवर्ती वर्ष में उसे नहीं दी जाएगी।

6. व्यय सीमा के अनुपालन का अवसर - (1) जहां पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में किसी विकास अधिकारी का वार्षिक पारिश्रमिक व्यय सीमा से अधिक है वहां उसकी सेवाएं मात्र उस आधार पर समाप्त नहीं की जाएगी यदि उसका मामला अवप्रेरणा सारणी में यथा उपबंधित सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से नियम 8 के उपबंधों के अधीन रहते हुए अवप्रेरणा देकर निपटारा जा सकता है, जिससे कि उसे व्यय सीमा के अनुपालन करने का अवसर प्रदान किया जा सके।

परंतु अवप्रेरणा सारणी के अनुसार अवप्रेरणा देने के प्रयोजन के लिए उसके कार्यपालन का वार्षिक पारिश्रमिक और उसको लागू विहित व्यय सीमा के प्रति निर्देश से मूल्य निर्धारण किया जाएगा।

अवप्रेरणा सारणी

क्रम सं.	जहां लागत अनुपात विहित सीमा से अधिक है	अवप्रेरणा जहां लागत अनुपात सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में विहित सीमा से अधिक है		
		प्रथम अवसर पर	द्वितीय क्रमिक अवसर पर	तृतीय और पश्चातवर्ती क्रमिक अवसर पर
1.	2 प्रतिशत से अधिक नहीं (परंतु मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 32 प्रतिशत से अधिक न हो)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2.	2 प्रतिशत से अधिक नहीं (परंतु मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 32 प्रतिशत से अधिक न हो)	कोई वेतनवृद्धि नहीं	कोई वेतनवृद्धि नहीं	कोई वेतनवृद्धि नहीं
3.	2 प्रतिशत से अधिक नहीं (परंतु मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 32 प्रतिशत से अधिक न हो)	कोई वेतनवृद्धि नहीं	कोई वेतनवृद्धि नहीं	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा एक वेतनह्रास
4.	जहां मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 32 प्रतिशत से अधिक है किन्तु 35 प्रतिशत से अधिक नहीं है	कोई वेतनवृद्धि नहीं	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा एक वेतनह्रास	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा दो वेतनह्रास
5.	जहां मूल्य निर्धारण वर्ष में लागत अनुपात 35 प्रतिशत से अधिक है	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा एक वेतनह्रास	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा दो वेतनह्रास	कोई वेतनवृद्धि नहीं तथा दो वेतनह्रास

टिप्पण - इस सारणी के प्रयोजन के लिए,-

- (क) “कोई वेतनवृद्धि नहीं” से वेतन वृद्धि का न दिया जाना अभिप्रेत है ।
 (ख) “वेतनह्रास” से एक या अधिक प्रक्रम/प्रक्रमों तक मूल वेतन में कमी करना अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण

(i) अवप्रेरणा सारणी का लागू किया जाना नियम 9 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन होगा परंतु यह तब जबकि विकास अधिकारी की सेवाएं इस नियम के उपनियम (2) या उपनियम (8) के अधीन समाप्त नहीं किया जा सकता है ।

(ii) अवप्रेरणा सारणी के प्रयोजन के लिए किसी विकास अधिकारी का वार्षिक पारिश्रमिक क्रमिक अवसर पर विहित व्यय सीमा पर अधिक तब माना जाएगा जब ऐसा पारिश्रमिक दो लगातार मूल्य निर्धारण वर्षों में ऐसी व्यय सीमा से अधिक रहता हो भले ही व्यय सीमा से आधिक्य का प्रतिशत भिन्न हो और किसी मूल्य निर्धारण वर्ष को भी जिसमें विकास अधिकारी व्यय सीमा पार करता है भले ही वहां कोई अवधारणा न हो, यह अभिनिश्चित करने के लिए हिसाब में लिया जाएगा कि क्या क्रमिक अवसरों पर व्यय सीमा पार हुई है और क्रमिक अवसरों पर अवप्रेरणा सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख के ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में विहित व्यय सीमा के आधिक्य के अनुरूप होगी ।

(iii) अवप्रेरणा सारणी को निरंतर लागू किया जाएगा यदि विहित व्यय सीमा के अनुपालन के पश्चात् विकास अधिकारी किसी पश्चातवर्ती तारीख को पुनः इसे पार कर जाता है ।

(2) यदि उपनियम (1) में अंतर्विष्ट उपबंधों के लागू किए जाने के फलस्वरूप निकाला गया मूल वेतन विकास अधिकारी के बारे में लागू ग्रेड के न्यूनतम से भी कम पड़ता है तो उसका मूल वेतन विकास अधिकारी को लागू ऐसे न्यूनतम पर नियत किया जाएगा :

परंतु इस उपनियम के अधीन न्यूनतम पर मूल वेतन का नियत किया जाना विकास अधिकारी की संपूर्ण सेवा के दौरान एक से अधिक बार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा और यदि दूसरे अवसर पर इस प्रकार निकाला गया मूल वेतन ऐसे न्यूनतम से कम पड़ता है तो उसकी सेवाएं नियम 7 के अनुसार समाप्त की जा सकेंगी ।

(3) जहां किसी विकास अधिकारी के मूल वेतन में उपनियम (1) या उपनियम (2) (जिसे इसमें इसके पश्चात् “पुनरीक्षित मूल वेतन” कहा गया है) के अधीन कमी की जाती है या नियत किया जाता है वहां उसे केवल ऐसे भत्ते और अन्य फायदे अनुज्ञात किए जाएंगे जो उस मूल वेतन पर अनुज्ञेय हैं :

परंतु वैयक्तिक भत्ता या अन्यथा मंजूर कर वार्षिक पारिश्रमिक को कोई संरक्षण नहीं दिया जाएगा ; और व्यय सीमा का तत्पश्चात् उसके द्वारा पालन करने के परिणामस्वरूप पिछली अवधि के लिए वेतन या किसी भत्ते का कोई बकाया संदेय नहीं होगा ।

(4) नियुक्त प्राधिकारी उपनियम (1), (2) और (3) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा और वह सुसंगत मूल्य निर्धारण वर्ष की समाप्ति की यथाशीघ्र पश्चात् उक्त उपनियमों में विनिर्दिष्ट विषयों को अवधारित करेगा :

परंतु संबद्ध प्राधिकारी इस नियम के अधीन किसी विषय का विनिश्चय करने के पूर्व विकास अधिकारी को अभ्यावेदन करने का अवसर प्रदान करेगा ।

(5) जहां उपनियम (4) के परंतुक के अधीन प्राप्त अभ्यावेदन से,

(क) आदेय प्रीमियम या अन्य आंकड़ों की संगणना करने में किन्हीं वास्तविक अशुद्धियों का पता चलता है तो सक्षम प्राधिकारी उल्लिखित आंकड़ों के अनुसार अपने आवश्यक सीमा तक अपने विनिश्चय की पुनरीक्षा करेगा और अभ्यावेदन का निपटान करने के लिए समुचित आदेश पारित करेगा ;

(ख) यदि व्यय सीमा की शिथिलता को उपयुक्त ठहराने के लिए अभ्यावेदन में ऐसे कारण का पता चलता है जो विकास अधिकारी के नियंत्रण के परे था जैसे दुर्घटना या बीमारी और यदि वह अभिवचन करता है कि अवप्रेरणा का अधिनिर्णय उस आधार पर प्रभावी नहीं किया जाना चाहिए तो सक्षम प्राधिकारी उस अभ्यावेदन का विनिश्चय करने के लिए क्षेत्रीय प्रबंधक को भेजेगा।

(6) यदि क्षेत्रीय प्रबंधक का यह समाधान हो जाता है कि अभ्यावेदन में कोई गुणागुण है तो वह मामले की तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगा और ऐसा आदेश पारित करेगा जो वह ठीक समझे।

(7) ऐसा विकास अधिकारी जिसका अभ्यावेदन क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा नामंजूर कर दिया गया है, उस मामले की बाबत अध्यक्ष को एक ज्ञापन प्रस्तुत कर सकेगा।

(8) उपनियम (1) से (7) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां किसी पूर्ववर्ती वर्ष में (जिसे इस उपनियम में इसके पश्चात् “सुसंगत वर्ष” कहा गया है) विकास अधिकारी का वार्षिक पारिश्रमिक उस वर्ष के आदेय प्रीमियम के 38 प्रतिशत से अधिक होता है और सुसंगत वर्ष में और सुसंगत वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में कुल वार्षिक पारिश्रमिक उन दो वर्षों में आदेय कुल प्रीमियम के 38 प्रतिशत से अधिक होता है तो उसकी सेवाएं नियम 7 के अनुसार समाप्त की जा सकेंगी।

(9) ऐसे विकास अधिकारी के मामले में जिनकी पुष्टि राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पूर्व तारीख को निगम की सेवाओं में हुई है, उपरोक्त उपनियम (8) में वर्णित प्रतिशतता समुचित संक्रमणकालीन रियायतों द्वारा बढ़ाई जाएगी और यह इस प्रकार होगी,-

(क) विकास अधिकारी की सेवाएं नियम 7 के अनुसार समाप्त की जा सकेंगी यदि राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् आरंभ हुए प्रथम मूल्य निर्धारण वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्रथम मूल्य निर्धारण वर्ष” कहा गया है) में उसका वार्षिक पारिश्रमिक उस वर्ष में आदेय प्रीमियम का 50 प्रतिशत से अधिक होता है और प्रथम मूल्य निर्धारण वर्ष और प्रथम मूल्य निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दो मूल्य निर्धारण वर्षों में कुल वार्षिक पारिश्रमिक उन तीन वर्षों में कुल आदेय प्रीमियम का 50 प्रतिशत से अधिक होता है।

(ख) विकास अधिकारी की सेवाएं नियम 7 के अनुसार समाप्त की जा सकेंगी यदि राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् आरंभ हुए द्वितीय मूल्य निर्धारण वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् “द्वितीय मूल्य निर्धारण वर्ष” कहा गया है) में उसका वार्षिक पारिश्रमिक उस वर्ष में आदेय प्रीमियम का 45 प्रतिशत से अधिक होता है और द्वितीय मूल्य निर्धारण वर्ष और द्वितीय मूल्य निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दो मूल्य निर्धारण वर्षों में कुल वार्षिक पारिश्रमिक उन तीन वर्षों में कुल आदेय प्रीमियम का 50 प्रतिशत से अधिक होता है।

(ग) विकास अधिकारी की सेवाएं नियम 7 के अनुसार समाप्त की जा सकेंगी यदि राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् आरंभ हुए तृतीय मूल्य निर्धारण वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् “तृतीय मूल्य निर्धारण वर्ष” कहा गया है) में उसका वार्षिक पारिश्रमिक उस वर्ष में आदेय प्रीमियम का 40 प्रतिशत से अधिक होता है और तृतीय मूल्य निर्धारण वर्ष और तृतीय मूल्य निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दो मूल्य निर्धारण वर्षों में कुल वार्षिक पारिश्रमिक उन तीन वर्षों में कुल आदेय प्रीमियम का 47.50 प्रतिशत से अधिक होता है।

(घ) विकास अधिकारी की सेवाएं नियम 7 के अनुसार समाप्त की जा सकेंगी यदि राजपत्र में इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् आरंभ हुए चतुर्थ मूल्य निर्धारण वर्ष (जिसे इसमें इसके पश्चात् “चतुर्थ मूल्य निर्धारण वर्ष” कहा गया है) में उसका वार्षिक पारिश्रमिक उस वर्ष में आदेय प्रीमियम का 38 प्रतिशत से अधिक होता है और चतुर्थ मूल्य निर्धारण वर्ष और चतुर्थ मूल्य निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती मूल्य निर्धारण वर्ष में कुल वार्षिक पारिश्रमिक उन दो वर्षों में कुल आदेय प्रीमियम का 38 प्रतिशत से अधिक होता है।

7. कतिपय दशाओं में सेवा की समाप्ति - (1) जहां कोई विकास अधिकारी व्यय सीमा का अनुपालन करने में असफल रहा है और जहां ऐसी सीमा का अनुपालन करने का नियम 7 के उपबंधों के अधीन कोई अवसर प्रदान नहीं किया जा सका था वहां जोन प्रबंधक तीन मास की सूचना या उसके बदले में वेतन देकर उसकी सेवाएं समाप्त कर सकता है :

परंतु विकास अधिकारी की उसकी प्रस्तावित सेवा समाप्ति के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश के विरुद्ध अपील, प्रबंध निदेशक को की जाएगी और कर्मचारिवृद्ध नियमों के नियम 41, 42, 43, 44 और 45 के उपबंध, जहां तक हो सके, वहां तक ऐसी अपील को लागू होंगे ।

(3) उपनियम (2) के अधीन अपील की जाने पर, प्रबंध निदेशक मामले के अभिलेख पर विचार करके और मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गुणागुण के आधार पर आदेश पारित कर सकेगा ।

8. अवप्रेरणा का आस्थगन - (1) “कोई वेतन वृद्धि नहीं” से भिन्न अवप्रेरणा सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख (जिसे इसमें इसके पश्चात् “सुसंगत देय तारीख” कहा गया है) से अधिनिर्णय नहीं की जाएगी किन्तु अनुवर्ती वर्ष की समाप्ति के पश्चात् तक आस्थगित रखी जाएगी, यदि किसी पूर्ववर्ती वर्ष में कोई विकास अधिकारी, जिसने कम से कम 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली है, ऐसी विहित व्यय सीमा पार कर चुका है, जिससे अवप्रेरणा-सारणी के अनुसार अवप्रेरणा दिया जाना आवश्यक हो जाता है :

परंतु यह तब जब कि ऐसे संसुगत मूल्य निर्धारण वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती दस वर्ष से अन्यून निरंतर अवधि तक विहित व्यय सीमा पर नहीं की है या जहां उसने दस वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है ।

(2) जहां विकास अधिकारी उस नियम (1) में निर्दिष्ट अनुवर्ती वर्ष में विहित सीमा का अनुपालन करता है वहां ऐसी अवप्रेरणाओं को जो आस्थगित रखी गई है, अधिनिर्णीत करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, और यदि कोई वेतन वृद्धि जो सुसंगत नियत तारीख को उसे अन्यथा प्रोदभूत हो गई होती, अवप्रेरणा के रूप में अनुज्ञात की गई थी तो ऐसी वेतनवृद्धि सुसंगत देय तारीख से निर्मोचित कर दी जाएगी ।

(3) जहां विकास अधिकारी किसी ऐसे अनुवर्ती वर्ष में विहित व्यय सीमा को पार कर चुका है वहां ऐसी अवप्रेरणा जो आस्थगित रखी गई है, सुसंगत देय तारीख से अधिनिर्णीत कर दी जाएगी और ऐसे अनुवर्ती वर्ष में उसको संदत्त अधिक्य पारिश्रमिक की समुचित वसूली आगामी वर्ष के उसके वेतन में से की जाएगी और “कोई वेतन वृद्धि नहीं” की अवप्रेरणा यदि कोई हो, अंतिम हो जाएगी और वह ऐसे अनुवर्ती वर्ष में विहित व्यय सीमा का अनुपालन करने में अपनी असफलता के लिए अवप्रेरणा सारणी के अनुसार कार्रवाई किए जाने का भी दायी हो जाएगा ।

(4) जहां अवप्रेरणाओं को उपनियम (2) के अनुसार प्रवर्तित नहीं किया जाता है या वेतनवृद्धि सुसंगत देय तारीख से निर्मोचित की जाती है वहां उपनियम (1) के अधीन पूर्ववर्ती वर्ष को, यथास्थिति, पांच वर्ष या तीन वर्ष की निरंतर-सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए उस वर्ष के रूप में नहीं माना जाएगा, जिसमें उसने विहित व्यय सीमा पार नहीं की है ।

13. जहां सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख 1.4.1988 को या उसके पश्चात् पड़ती है, वहां मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप अवप्रेरणा - सारणी के अनुसार मूल वेतन में की गई कमी का पुनःस्थापन -

(1) 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् पड़ने वाली सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप किसी विकास अधिकारी के मूल वेतन में की गई कमी (जिसे इसमें इसके पश्चात् “चालू वेतनह्रास” कहा गया है) को इस नियम या नियम 10 के उपबंधों के अनुसार पुनः स्थापित किया जा सकेगा ।

(2) जहां कोई विकास अधिकारी इस नियमों के अनुसार पुनः स्थापन के लिए अर्हित करता है वहां मूल वेतन में कमी जो पहली बार 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् की गई थी, प्रथमतः पुनःस्थापित की जाएगी ; मूल वेतन में कमी जो तत्पश्चात् की गई थी, अगली बार पुनः स्थापित की जाएगी और इस प्रकार की जाती रहेगी :

परंतु यदि कोई विकास अधिकारी उस मूल्य निर्धारण तारीख के जिससे उसके मूल वेतन में कमी की गई थी, आगामी पांच मूल्य निर्धारण वर्षों के भीतर पुनः स्थापन के लिए अर्हित होने में असफल रहता है तो उस कमी का कोई पुनःस्थापन नहीं किया जाएगा और उस दशा में कुल मूल वेतन में अगली कमी, यदि कोई हो, पुनःस्थापन के लिए देय मानी जाएगी यदि वह बाद में पुनः स्थापन के लिए अर्हित हो जाता है ।

परंतु यह और कि इस नियम और नियम 10 के अधीन मूल वेतन में कमी का पुनःस्थापन विकास अधिकारी के रूप में पूर्ण सेवा अवधि के दौरान केवल तीन अवसरों तक सीमित रहेगा ।

(3) उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि 1 अप्रैल 1988 को या उसके पश्चात् पड़ने वाली किसी सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को मूल्य निर्धारण तारीख से यह प्रकट होता है कि किसी विकास अधिकारी ने पूर्ववर्ती वर्ष में व्यय सीमा पार नहीं की है और यह कि ऐसे पूर्ववर्ती वर्ष और अगले दो पूर्ववर्ती वर्षों में लागत अनुपात कुल मिलाकर उन तीन वर्षों के लिए (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् तीन वर्ष का ब्लाक कहा गया है) सम्मिलित व्यय सीमा से अधिक नहीं है तो आदेय चालू वेतनहास सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से पुनः स्थापित किया जाएगा :

परंतु किसी पूर्ववर्ती वर्ष में विकास अधिकारी व्यय सीमा का अनुपालन नहीं करता है तो वह पुनः स्थापन के लिए तब अर्हित हो सकेगा जब किसी पश्चात्वर्ती सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को तीन वर्षों का ब्लाक हो :

परंतु यह और कि एक वर्ष से अनधिक से संबंधित चालू वेतनहास का एक सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख को पुनः स्थापन किया जाएगा भले ही भावी लागत एक वर्ष से अधिक वेतनहास के पुनः स्थापन का समर्थन करे ।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजनों के लिए -

(i) “तीन वर्ष का ब्लाक” से अभिप्रेत है ऐसा प्रत्येक पूर्ववर्ती वर्ष जिसमें विकास अधिकारी ने व्यय सीमा पार नहीं की है और अगले दो पूर्ववर्ती वर्ष ;

(ii) “आदेय चालू वेतनहास” से एक वर्ष से संबंधित चालू वेतनहास अभिप्रेत है जो यदि पुनः स्थापित किया गया, तो फिर भी भावी लागत को अधिकतम सीमा के अंतर्गत रखेगा ;

(iii) “भावी लागत” से वह अनुपात अभिप्रेत है जो सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख (जिसके अंतर्गत उस तारीख की ओर से सभी वेतनवृद्धियां और प्रस्तावित पुनः स्थापन भी हैं) को किसी विकास अधिकारी को लागू वार्षिक पारिश्रमिक का पूर्ववर्ती वर्ष की आदेय प्रीमियम से है और भावी लागत को अधिकतम सीमा के अंतर्गत समझा जाएगा यदि किसी विकास अधिकारी को लागू ऐसा पारिश्रमिक ऐसे आक्षेप प्रीमियम के उसके व्यय सीमा के प्रतिशत से अधिक रही है ।

(4) कोई पुनः स्थापन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा यदि पुनः स्थापन पर विकास अधिकारी वेतनमान के ऐसे प्रक्रम पर पहुंचता है जिसपर वह उस आधार पर न पहुंचता यदि उसने व्यय सीमा पार न की होती और ऐसी दशा में पुनः स्थापन वेतनमान के ऐसे प्रक्रम तक सीमित होगा जहां तक वह प्रसामान्यतः पहुंचता ।

10. जहां सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख 1 अप्रैल, 1988 को या उसके पश्चात् पड़ती है वहां मूल्य निर्धारण के परिणामस्वरूप अवप्रेरणा सारणी के अनुसार मूल वेतन में की गई कमी का पुनः स्थापन - अनुकल्पी रीति -

नियम 9 के उपनियम (2) और उपनियम (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए यदि कोई विकास अधिकारी तीन क्रमवर्ती मूल्य निर्धारण वर्षों में व्यय सीमा पार नहीं करता है तो एक वर्ष से संबंधित चालू वेतनहास ऐसे पिछले मूल्य निर्धारण वर्ष की ठीक आगामी सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से पुनः स्थापित किया जा सकेगा ।

11. भविष्य निधि - (1) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1986 के नियम 8 में किसी बात के होते हुए भी, जहां नियम 9 या 10 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार सुसंगत मूल्य निर्धारण तारीख से किसी विकास अधिकारी को पिछले वेतनहास या चालू वेतनहास प्रत्यावर्तित या पुनः स्थापित किए जाते हैं । वहां नियम अपने द्वारा स्थापित भविष्य निधि में (जिसे इसमें इसके पश्चात् “निधि” कहा गया है) में उस अवधि के संबंध में जिसके लिए ऐसे वेतनहास प्रत्यावर्तित या पुनः स्थापित किए गए हैं, ऐसे वेतनहासों में समाविष्ट मूल वेतन के कुल योग का 10 प्रतिशत की अधिकतम रकम का अभिदाय करेगा :

परंतु यदि उस अवधि के दौरान या उस अवधि के किसी भाग के दौरान जिसमें उक्त वेतनहास प्रवृत्त थे वह दर जिस पर नियोजक का अभिदाय 10 प्रतिशत से अधिक था तो निगम सुसंगत अवधि से संबंधित मूल वेतन के उस भाग में ऐसी अधिक दर पर अभिदाय कर सकेगा :

परंतु यह और कि विकास अधिकारी निधि में निगम से अपेक्षित अभिदायों के बराबर रकम का निधि के नियमों के अनुसार और उस रीति में जिसका उसे निगम द्वारा निदेश दिया गया हो, अपने अतिरिक्त अभिदाय के रूप में अभिदाय करेगा ।

(2) निगम निधि में तब और उस विस्तार तक जिस तक विकास अधिकारी उपनियम (1) के द्वितीय परंतुक के अधीन ऐसे अतिरिक्त अभिदाय करता है, अभिदाय करेगा।

(3) उपनियम (1) के अधीन निगम द्वारा किए गए अभिदाय किसी ऐसे प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे जिसके लिए नियोजक के अभिदाय निधि के नियमों के अधीन उपलब्ध नहीं है।

(4) इस नियम की कोई बात ऐसे किसी विकास अधिकारी को लागू नहीं होगी जो निगम द्वारा अनुमोदित किसी अधिवार्षिकी निधि में अभिदाय कर रहा है।

12. विशेष मामले - प्रबंध निदेशक, क्षेत्रीय प्रबंधक की सिफारिश पर, अवप्रेरणा सारणी के अनुसरण में मूल वेतन में कमी की तारीख के पश्चात् किसी विकास अधिकारी के किसी मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा यदि वह नियम 9 या नियम 10 के अधीन पुनः स्थापन के लिए अर्हित नहीं करता है और मामले के गुणागुण की ध्यान में रखते हुए ऐसा अनुतोष प्रदान कर सकेगा किन्तु उस अनुतोष से अधिक नहीं होगा जो उसे तब अनुज्ञेय होता जब वह पुनः स्थापन के लिए उक्त नियमों में से किसी के अधीन स्वयं को अर्हित करता।

13. प्रेरणा - निगम द्वारा अनुमोदित किसी स्कीम के अधीन प्रेरणा बोनस किसी पूर्ववर्ती वर्ष के लिए किसी विकास अधिकारी को समय-समय पर मंजूर की जा सकेगी।

14. विकास अधिकारी की प्रोन्नति - योग्य समझे जाने वाले किसी भी विकास अधिकारी की प्रोन्नति कर्मचारिवृद्ध नियमों के नियम 7 के अनुसार सहायक शाखा प्रबंधक या सहायक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में की जा सकती है।

15. सेवा समाप्त विकास अधिकारी की पुनर्नियुक्ति - यदि किसी ऐसे विकास अधिकारी ने जिसकी सेवाओं को नियम 7 के अनुसरण में समाप्त किया गया है, ऐसी सेवा समाप्ति की तारीख को वर्ग-2 में कम से कम सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली है और 55 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है तो वह ऐसी अर्हता और योग्यता के अनुसार जो भारतीय जीवन बीमा निगम (सेवा समाप्त विकास अधिकारी की पुनर्नियुक्ति) नियम, 1990 के अधीन विनिर्दिष्ट की जाए, वर्ग-3 में प्रशासनिक कार्य करने के लिए सहायक यसा अधिलेख लिपिक के रूप में नियम की सेवा में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होगा :

परंतु सेवा समाप्ति के परिणामस्वरूप सेवा में व्यवधान के होते हुए भी नियम में उसकी सेवा छुट्टी के प्रयोजन के लिए निरंतर मानी जाएगी और उपदान या भविष्य निधि के प्रयोजन के लिए भी यदि उसने वह प्राप्त नहीं की है और यदि उसने प्राप्त की है किन्तु वह निगम को उपदान या भविष्य निधि की ऐसी रकम का संदाय करता है जो उससे प्राप्त की है।

16. निरसन और व्यावृत्ति - (1) भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 को निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी निर्धारण वर्ष जो इन नियमों के प्रकाशन की तारीख के पूर्व प्रारंभ हो गया है, भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 के उपबंध उस निर्धारण वर्ष को लागू होंगे मानो उक्त नियमों को निरसित न किया गया हो।

(3) ऐसे निरसन के होते हुए भी भारतीय जीवन बीमा निगम विकास अधिकारी (सेवा के कतिपय निबंधनों और शर्तों का पुनरीक्षण) नियम, 1989 के अधीन बनाया गया कोई नियम, की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इन नियमों के अधीन बनाई गई या की गई समझी जाएगी।

(4) इन नियमों की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह कर्मचारिवृद्ध नियमों के अनुसार किसी विकास अधिकारी को सेवान्युक्त करने, सेवानिवृत्त करने या उसकी सेवाओं को अवधारित करने के सक्षम प्राधिकारी के अधिकार पर प्रभाव डालता है या भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारिवृद्ध) नियम, 1960 (जिसे इसमें इसके पश्चात् कर्मचारिवृद्ध नियम कहा गया है) के अनुसार उसमें विनिर्दिष्ट किन्हीं आधारों पर उस पर कोई शास्ति अधिरोपित करने के सक्षम प्राधिकारी के अधिकार को प्रभावित करती है या ऐसे मामलों की बाबत जो इन नियमों में उल्लिखित नहीं हैं विकास अधिकारियों के कर्मचारिवृद्ध नियमों पर लागू होती है।

16 निर्वाचन अध्यक्ष समय-समय पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकेगा जो नियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने और क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक समझे। जहाँ इन नियमों के निर्वाचन की बाबत कोई संदेह या कठिनाई पैदा होती है वहाँ वह विनिश्चय के लिए केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट की जाएगी।

[फा. सं. एस-11012/02/2008-बीमा III]

तरुण बजाज, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2009

G.S.R. 818(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (cc) of sub-section (2), of section 48 of the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules regulating certain terms and conditions of service relating to business performance of Development Officers of the Life Insurance Corporation of India, namely:-

1. Short title and Commencement.- (1) These rules may be called the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires;

(a) "Act" means the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956);

(b) "annual remuneration" means the basic pay, special pay, personal pay, dearness allowance, and all other allowances and non-profit sharing or ex-gratia bonus due to, or paid to, a Development Officer during the appraisal year and includes the expenses payable or reimbursed to him or incurred by the Corporation during that year in respect of traveling, residential telephone, mobile, insurance premium and taxes on motor vehicles, but does not include incentive bonus paid to him in accordance with rule 13;

(c) "appraisal date" means –

(i) in relation to a Development Officer appointed on or after the date of publication of these rules in the Official Gazette,

- (A) in the first year of his service, the first day of the month following that in which he completes twelve months of service from the date of his appointment; and
 - (B) in every subsequent year of his service, the first day of the month following that in which he completes twelve months of service from the last appraisal date;
- (II) in relation to a Development Officer appointed prior to the date of publication of these rules in the Official Gazette,
- (A) in the first year of his service from the date of publication of these rules in the Official Gazette the 1st day of the month following that in which he completes a period of twelve months of service from the date on which his last annual increment accrued (whether released or not) in accordance with sub-rule (2) of rule 56 of the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960, and
 - (B) in every subsequent year of service, the first day of month following that in which he completes twelve months of service from the last appraisal date;
 - (d) "appraisal year" means the period between two consecutive appraisal dates and the period of twelve months of service preceding the appraisal date ascertained in accordance with item (A) of sub-clause (I) of clause (c), and each period of twelve months of service next preceding the appraisal date ascertained in accordance with item (A) of sub-clause (II) of clause (c), shall also be an appraisal year;
 - (e) "cost ratio" in relation to a Development Officer means the ratio which his annual remuneration in any year bears to the eligible premium of that year and expressed as a percentage of such eligible premium;
 - (f) "decrement" means reduction in basic pay by one or more stages in the scale of pay on one or more occasions;
 - (g) "Development Officer" means a whole-time salaried employee of the Corporation belonging to Class II appointed as a Development Officer;
 - (h) "disincentive" means non grant of increment or decrement/s as provided in the Table of Disincentive;
 - (i) "eligible premium" means such proportion as may be specified by the Corporation from time to time on the first year's premiums received by the Corporation in respect of the business secured by the agents in the organisation of a Development Officer, which is adjusted in the relevant appraisal year;

- (j) "expense limit" in respect of an appraisal year in relation to a Development Officer working in an operational area specified in column (1) of the Table below (hereinafter referred to as the "Table of Expense Limit") means the percentage of the eligible premium of that year as specified in the corresponding entry in column (2) thereof and it shall apply to the Development Officers who have been confirmed in the services of the Corporation on a date prior to the date of publication of these rules in the Official Gazette:-

TABLE OF EXPENSE LIMIT

If the Development Officer is working in operational area	Percentage of eligible premium
(1)	(2)
A	19%
B	20%
C	21%
D	22%

Provided that in respect of a Development Officer who has been confirmed in service on or after the date of publication of these rules in the Official Gazette, the expense limit applicable shall be as specified in the Table below:

TABLE OF EXPENSE LIMIT

If the Development Officer is working in operational area	Percentage of eligible premium		
	In the first appraisal year after confirmation	In the second appraisal year after confirmation	In the third and subsequent appraisal years after confirmation
(1)	(2)	(3)	(4)
A	22%	21%	19%
B	23%	22%	20%
C	24%	23%	21%
D	25%	24%	22%

Note:

- (1) The expense limit of a Development Officer for any appraisal year is expressed as a percentage of the eligible premium of that year; a Development Officer is said to exceed the expense limit if his annual remuneration in that year is in excess of the expense limit; such excess or

the ratio which such annual remuneration bears to the eligible premium of that year may also be expressed as a percentage of the eligible premium;

- (2) In the case of a Development Officer who has been confirmed in the services of the Corporation on a date prior to the date of publication of these rules in the Official Gazette, the percentage specified in the above Table shall be increased by the appropriate transitional concessions, if any, as defined in clause (t):

Provided that the transitional concessions shall not apply to those Development Officers who are governed under rule 4.

- (k) "operational area" with reference to a Development Officer means the area in which he is posted to work as Development Officer and the area is said to be his operational area, if, -

(A) he is working in a City or Urban agglomeration or Town with an ascertained population of more than 10 lakhs;

(B) he is working in a City or Urban agglomeration or Town with an ascertained population of 6 lakhs or above but not more than 10 lakhs;

(C) he is working in a City or Urban agglomeration or Town with an ascertained population of less than 6 lakhs; and

(D) he is working in a rural area or remote rural area or any hilly area specified in Explanation (2) and (3) or any other hilly area which the Central Government may in consultation with the Corporation by notification in the Official Gazette specify in this behalf;

Explanation: For the purpose of this clause, -

- (1) "ascertained population" means the population as ascertained from the latest Census Report of the Government of India;

- (2) A Development Officer is said to be working in a "rural area" or "remote rural area" if his headquarters is at a place with an ascertained population of 50,000 or less and his operational area has an ascertained population of not more than 1.5 lakhs;

- (3) A Development Officer is said to be working in a "hilly area" if his headquarter is at a place situated at a height of 1000 metres and over, above mean sea level.

- (l) "preceding year" or "relevant appraisal year" means the appraisal year immediately preceding the relevant appraisal date;

- (m) "prescribed expense limit" or "prescribed cost ratio" means the increased expense limit ascertained in accordance with rule 4, where such expense limit is applicable to a Development Officer, or if it is not so applicable to him, the expressions shall mean the expense limit applicable to him;
- (n) "relevant appraisal date" means the appraisal date on which the performance of the Development Officer for the appraisal year immediately preceding that date is assessed for any purpose under these rules or was assessed hitherto under the staff rules;
- (o) "service" means the period spent on duty as a Development Officer and leave including extra-ordinary leave which has been condoned under sub-rule (4) of rule 69 of the staff rules;
- (p) "staff rules" means the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960;
- (q) "succeeding year" means the period of twelve months commencing from the relevant appraisal date;
- (r) "Table of Disincentives" means the Table as appended in sub-rule (1) of rule 6;
- (s) "Increased Expense Limit" means the Expense Limit as mentioned in rule 4.
- (t) "transitional concession" means the concession as specified in the Table below applicable to a Development Officer who has been confirmed in the services of the Corporation on a date prior to the date of publication of these rules in the Official Gazette:

TABLE

Operational Area as defined in clause (l) of rule 2 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989	A	B	C	D	E
Expense Limit as provided in the Table of Expense Limit in clause (k) of rule 2 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989 so repealed shall be taken as base for providing transitional concessions for the subsequent years based on the date of publication of	22%	23%	24%	25%	26%

these rules in the Official Gazette and subsequent years mentioned as under:					
a) Expense Limit applicable in the First appraisal year	21%	22%	23%	24%	25%
b) Expense Limit applicable in the Second appraisal year	20%	21%	22%	23%	24%
c) Expense Limit applicable in the Third appraisal year	19%	20%	21%	22%	22%

(u) words and expressions used and not defined herein but defined in the staff rules shall have the meanings respectively assigned to them in those staff rules.

3. **Tenure.**- Subject to the provisions of these rules, a Development Officer shall hold office by the same tenure and in the same manner as any other class of employee in the Corporation:

Provided that he shall conform to the expense limit applicable to him:

Provided further that the services of a confirmed Development Officer shall not be terminated on the ground of poor business production resulting in cost ratio in excess of the expense limit applicable to him, unless he has been given an opportunity to conform to the expense limit as provided in rule 6.

4. **Expense limit applicable to Development Officers.**- (1) The expense limit applicable to a Development Officer shall be as specified in the Table of Expense Limit as provided in clause (j) of rule 2 and it shall be the expense limit applicable to his operational area as increased by two percent, if, at or before such commencement of the relevant appraisal year, he has completed the age of 55 years;

Provided that the increased expense limit specified in the sub-rule (1) shall apply to relevant appraisal date commencing after the date of publication of these rules in the Official Gazette in respect of operational areas 'A', 'B', 'C' and 'D'

(2) In respect of a Development Officer who has been confirmed on a date prior to the date of publication of these rules in the Official Gazette and who has put in more than ten years of service as a Development Officer at the commencement of the relevant appraisal year.-

- (a) the expense limit applicable in the first, second and third appraisal years shall be as provided in the Table as under, if he has completed 50 years of age and not completed 52 years, at or before such commencement of the relevant appraisal year:

TABLE

Operational Area as defined in clause (I) of rule 2 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989	A	B	C	D	E
Expense Limit as provided in the Table of Expense Limit in clause (1) of rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989 so repealed shall be taken as base for providing transitional concessions for the subsequent years based on the date of publication of these rules in the Official Gazette and subsequent years mentioned as under:	23%	24%	25%	26%	27%
a) Expense Limit applicable in the First appraisal year	22%	23%	24%	25%	26%
b) Expense Limit applicable in the Second appraisal year	21%	22%	23%	24%	24%
c) Expense Limit applicable in the Third appraisal year	19%	20%	21%	22%	22%

- (b) the expense limit applicable in the first, second and third appraisal years shall be as under, if he has completed 52 years of age and not completed 53 years, at or before such commencement of the relevant appraisal year:

Operational Area as defined in clause (I) of rule 2 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989	A	B	C	D	E
Expense Limit as provided in the Table of Expense Limit in clause (1) of	24%	25%	26%	27%	28%

rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989 so repealed shall be taken as base for providing transitional concessions for the subsequent years based on the date of publication of these rules in the Official Gazette and subsequent years mentioned as under:					
a) Expense Limit applicable in the First appraisal year	23%	24%	25%	26%	27%
b) Expense Limit applicable in the Second appraisal year	21%	22%	23%	24%	25%
c) Expense Limit applicable in the Third appraisal year	19%	20%	21%	22%	22%

- (c) the expense limit applicable in the first, second and third appraisal years shall be as under, if he has completed 53 years of age and not completed 54 years, at or before such commencement of the relevant appraisal year:

Operational Area as defined in clause (l) of rule 2 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989	A	B	C	D	E
Expense Limit as provided in the Table of Expense Limit in clause (1) of rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989 so repealed shall be taken as base for providing transitional concessions for the subsequent years based on the date of publication of these rules in the Official Gazette and subsequent years mentioned as under:	24%	25%	26%	27%	28%
a) Expense Limit applicable in the First appraisal year	23%	24%	25%	26%	27%
b) Expense Limit applicable in the Second appraisal year	22%	23%	24%	25%	26%

c) Expense Limit applicable in the Third appraisal year	21%	22%	23%	24%	24%
---	-----	-----	-----	-----	-----

(d) the expense limit applicable in the first, second and third appraisal years shall be as under, if he has completed 54 years of age, at or before such commencement of the relevant appraisal year:

Operational Area as defined in clause (i) of rule 2 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989	A	B	C	D	E
Expense Limit as provided in the Table of Expense Limit in clause (1) of rule 4 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989 so repealed shall be taken as base for providing transitional concessions for the subsequent years based on the date of publication of these rules in the Official Gazette and subsequent years mentioned as under:	25%	26%	27%	28%	29%
a) Expense Limit applicable in the First appraisal year	24%	25%	26%	27%	28%
b) Expense Limit applicable in the Second appraisal year	22%	23%	24%	25%	26%
c) Expense Limit applicable in the Third appraisal year	21%	22%	23%	24%	24%

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1) and (2) of rule 4 the percentage specified in column (2) of the Table of Disincentives as provided in sub rule (1) of rule 6 or the percentages specified in sub-rules (8) and (9) of rule 6 shall not be increased.

5. **Increments.**— (1) Increments shall ordinarily be drawn by a Development Officer as a matter of course in accordance with rule 56 of the staff rules, unless he has reached the maximum of the grade or the increment cannot

be allowed in accordance with rule 6 or it is withheld as a disciplinary measure under rule 39 of the staff rules.

- (2) Where no increment is granted to a Development Officer in any year in accordance with rule 6 as a disincentive, such increment shall not be granted to him in any subsequent year, except in accordance with the provisions contained in rule 8.

- 6. Opportunity to conform to the expense limit.-** (1) Where the annual remuneration of any Development Officer in the preceding year or years is in excess of the expense limit, his services shall not be terminated merely on that ground if his case is capable of being dealt with by awarding disincentives, subject to the provisions of rule 8, from the relevant appraisal date as provided in the Table of Disincentives, so as to afford him an opportunity to conform to the expense limit:

Provided that for the purpose of award of disincentives in accordance with the Table of Disincentives, his performance shall be appraised with reference to the annual remuneration and the prescribed expense limit applicable to him.

Table of Disincentives

Sl. No.	Where the cost ratio is in excess of prescribed limit.	Disincentives where the cost ratio is in excess of prescribed limit in the appraisal year next preceding the relevant appraisal date.		
		On the first occasion	On the second successive occasion	On the third and subsequent successive occasion
1.	By not more than 2% (Provided that the cost ratio in the appraisal year is not more than 32%).	NIL	NIL	NIL
2.	By more than 2% but not more than 4% (Provided that the cost ratio in the appraisal year is not more than 32%).	No Increment	No Increment	No Increment
3.	By more than 4% (Provided that the cost ratio in the appraisal year is not more than 32%).	No Increment	No Increment	No Increment and one decrement.

4.	Where the cost ratio in the appraisal year is more than 32% but not more than 35%.	No Increment	No Increment and one decrement.	No Increment and two decrements.
5.	Where the cost ratio in the appraisal year is more than 35%.	No Increment and one decrement.	No Increment and two decrements.	No Increment and two decrements.

Note:

For the purposes of this Table:-

- (a) "no increment" means non grant of increment;
- (b) "decrement" means reduction in basic pay by one or more stage/s.

Explanation:

- (i) The application of Table of Disincentives shall be subject to the provisions contained in rule 8 provided the services of the Development Officer are not liable to be terminated under sub-rule (2) or sub-rule (8) of this rule.
- (ii) For the purpose of the Table of Disincentives, the annual remuneration of a Development Officer shall be deemed to be in excess of the prescribed expense limit on a successive occasion if such remuneration exceeds such expense limit in two consecutive appraisal years even though the excess percentage over the prescribed expense limit may vary and an appraisal year in which the Development Officer exceeds the prescribed expense limit even though there is no disincentive shall be reckoned for ascertaining whether the expense limit is exceeded on successive occasions and the disincentive on the successive occasion shall correspond to the excess of the prescribed expense limit in the appraisal year next preceding the relevant appraisal date.
- (iii) The Table of Disincentives shall be repeatedly applied, if, after conforming to the prescribed expense limit, the Development Officer exceeds it again at a later date.
- (2) If, as a consequence of the application of the provisions contained in sub-rule (1) the basic pay arrived at falls below the minimum of the grade applicable to the Development Officer, his basic pay shall be fixed at such minimum as applicable to Development Officer:

Provided that the fixation of basic pay at minimum under this sub-rule shall not be allowed more than once during the entire service of a Development Officer and if, on a second occasion, the basic pay so arrived at falls

below such minimum, his services shall be liable to be terminated in accordance with rule 7.

- (3) Where the basic pay of a Development Officer is reduced or fixed under sub-rule (1) or sub-rule (2) (hereinafter referred to as "the revised basic pay"), he shall be allowed only such allowances and other benefits as are admissible on that basic pay:

Provided that there shall be no protection of the annual remuneration either by granting a personal allowance or otherwise; and no arrears of pay or any allowance for the past period consequent on his conforming to the expense limit later on shall be payable.

- (4) The appointing authority shall be the competent authority for implementing the provisions of sub-rules (1), (2) and (3) and it shall determine the matters specified in the said sub-rules, as soon as may be, after the expiry of the relevant appraisal year:

Provided that the competent authority concerned shall, before deciding any matter under this rule, give an opportunity to the Development Officer to make a representation.

- (5) Where the representation received under proviso to sub-rule (4) discloses,

- (a) any factual inaccuracies in the computation of eligible premium or other figures, the competent authority shall revise his decision to the extent it is warranted by the revised figures and pass appropriate orders disposing of the representation;
- (b) any cause beyond the control of the Development Officer, such as accident or sickness which warrants relaxation on the expense limit and he pleads that the award of disincentives should not be effected on that ground, the competent authority shall forward the representation to the Zonal Manager, for decision.

- (6) If the Zonal Manager is satisfied that there is any merit in the representation, he may consider the facts and circumstances of the case and pass such orders as he may deem fit.

- (7) A Development Officer whose representation has been rejected by the Zonal Manager may submit a Memorial to the Chairman in respect of that matter.

- (8) Notwithstanding anything contained in sub rules (1) to (7) where the annual remuneration of a Development Officer in any preceding year (hereafter in this sub-rule referred to as the "relevant year") exceeds 38% of the eligible premium of that year and the aggregate of the annual

remuneration in the relevant year and the appraisal year immediately preceding the relevant year exceeds 38% of the aggregate of the eligible premium in those two years, his services shall be liable to be terminated in accordance with rule 7.

- (9) In the case of a Development Officer who has been confirmed in the services of the Corporation on a date prior to the date of publication of these rules in the Official Gazette, the percentage mentioned in sub-rule (8) above shall be increased by the appropriate transitional concessions, and it shall be as under, -

- (a) The services of a Development Officer shall be liable for termination in accordance with rule 7, if his annual remuneration in the First appraisal year commencing after the date of publication of these rules in the Official Gazette (hereinafter referred to as the "first appraisal year") exceeds 50% of the eligible premium in that year and the aggregate of the annual remuneration in the first appraisal year and the two appraisal years immediately preceding the first appraisal year exceeds 50% of the aggregate of the eligible premium in those three years.
- (b) The services of a Development Officer shall be liable for termination in accordance with rule 7, if his annual remuneration in the Second appraisal year commencing after the date of publication of these rules in the Official Gazette (hereinafter referred to as the "second appraisal year") exceeds 45% of the eligible premium in that year and the aggregate of the annual remuneration in the second appraisal year and the two appraisal years immediately preceding the second appraisal year exceeds 50% of the aggregate of the eligible premium in those three years.
- (c) The services of a Development Officer shall be liable for termination in accordance with rule 7, if his annual remuneration in the Third appraisal year commencing after the date of publication of these rules in the Official Gazette (hereinafter referred to as the "third appraisal year") exceeds 40 % of the eligible premium in that year and the aggregate of the annual remuneration in the third appraisal year and the two appraisal years immediately preceding the third appraisal year exceeds 47.50% of the aggregate of the eligible premium in those three years.
- (d) The services of a Development Officer shall be liable for termination in accordance with rule 7, if his annual remuneration in the Fourth appraisal year commencing after the date of publication of these rules in the Official Gazette (hereinafter referred to as the "fourth appraisal year") exceeds 38% of the eligible premium in that year and the aggregate of the annual remuneration in the fourth appraisal year and the appraisal year immediately preceding the fourth appraisal year exceeds 38% of the aggregate of the eligible premium in those two years.

7. **Termination of service in certain cases.-** (1) Where a Development Officer has failed to conform to the expense limit and where no opportunity to conform to such limit could be given under the provisions of rule 6, the Zonal Manager may terminate his services after giving him three months notice or salary in lieu thereof:

Provided that the Development Officer shall be given an opportunity to show cause against such proposed termination of his service.

- (2) An appeal against an order passed under sub-rule (1) shall lie to the Managing Director and the provisions of rules 41, 42, 43, 44 and 45 of the staff rules shall, so far as may be, apply to any such appeal.
- (3) In the case of an appeal under sub-rule (2), the Managing Director shall consider the records of the case and pass orders on merits having regard to the circumstances of the case.

8. **Deferment of Disincentives.-** (1) The disincentives, other than "no increment", shall not be awarded from the relevant appraisal date (hereinafter referred to as "the relevant due date"), but shall be kept in abeyance until after the expiry of the succeeding year, if, in any preceding year a Development Officer, who has completed at least ten years of service, has exceeded the prescribed expense limit attracting disincentives in accordance with the Table of Disincentives.

Provided that he has not exceeded the prescribed expense limit for a continuous period of not less than ten years immediately preceding such relevant appraisal year.

- (1) Where the Development Officer conforms to the prescribed expense limit in the succeeding year, referred to in sub-rule (1), no action shall be taken to award the disincentives which have been kept in abeyance, and if the increment, which would have been otherwise accrued to him on the relevant due date, had been disallowed as a disincentive, such increment shall be released from the relevant due date.
- (2) Where the Development Officer exceeds the prescribed expense limit in such succeeding year, the disincentives which have been kept in abeyance shall be awarded from the relevant due date and appropriate recovery of the excess remuneration paid to him in such succeeding year shall be made from his salary for the following year and the disincentive if any of "no increment" shall become final and he shall also be liable for action in accordance with the Table of Disincentives for his failure to conform to the prescribed expense limit in such succeeding year.

- (3) Where the disincentives are not enforced or the increment is released from the relevant due date in accordance with sub-rule (2), the preceding year under sub-rule (1) shall not be regarded as a year in which he has not exceeded the prescribed expense limit for the purpose of computing the continuous service of ten years, in which he has not exceeded the prescribed expense limit.

9. Reinstatement of reduction in basic pay effected in accordance with the Table of Disincentives as a result of appraisal where the relevant appraisal falls on or after 1st day of April, 1988.-

- (1) The reduction effected in the basic pay of a Development Officer as a result of appraisal on the relevant appraisal date falling on or after the 1st day of April, 1988 (hereinafter referred to as "current decrements") may be reinstated in accordance with the provisions of this rule or rule 10.
- (2) Where a Development Officer qualifies for reinstatement in accordance with this rule, the reduction in basic pay which was first effected on or after the 1st day of April, 1988 shall first be reinstated; the reduction in basic pay which was effected thereafter shall be reinstated next and so on:

Provided that if a Development Officer fails to qualify for reinstatement within five appraisal years following the appraisal date from which his basic pay was reduced, there shall be no reinstatement of that reduction, and in that case the next reduction, if any, in basic pay shall be regarded as due for reinstatement if he subsequently qualifies for reinstatement:

Provided further that the reinstatement of reduction in basic pay under this rule and rule 10 shall be limited to only three occasions throughout the service as a Development Officer.

- (3) Subject to the provisions of sub-rule (4), if on any relevant appraisal date falling on or after the 1st day of April, 1988, the appraisal discloses that a Development Officer has not exceeded the expense limit in the preceding year and that the cost ratio in such preceding year and the next two preceding years taken together does not exceed the combined expense limit for those three years (hereinafter referred to as a "block of three years") the eligible current decrement/s may be reinstated with effect from the relevant appraisal date:

Provided that in any preceding year, a Development Officer does not conform to the expense limit, he may qualify for reinstatement if there arises a block of three years on any subsequent relevant appraisal date:

Provided further that current decrement/s pertaining to not more than one year shall be reinstated on one relevant appraisal date, even though the

future cost may support reinstatement of decrement/s in excess of one year.

Explanation: For the purposes of this rule,

- (i) "block of three years" means every preceding year in which the Development Officer has not exceeded the expense limit and the next two preceding years;
 - (ii) "eligible current decrement/s" means the current decrement/s pertaining to one year which if reinstated shall still keep the future cost within ceiling;
 - (iii) "future cost" means the ratio which the annual remuneration applicable to a Development Officer on the relevant appraisal date (inclusive of all increments and proposed reinstatement on and from that date) bears to the eligible premium of the preceding year and the future cost shall be deemed to be within ceiling, if such annual remuneration applicable to a Development Officer is not in excess of his expense limit percentage (inclusive of transitional concessions, if any) of such eligible premium.
- (4) No reinstatement shall be allowed if, on reinstatement, the Development Officer shall reach a stage in the scale of pay which he would not have reached on the ground that he had exceeded the expense limit, and in such a case the reinstatement shall be limited to the stage in the scale of pay which he would have normally reached.

10. Reinstatement of reduction in basic pay effected in accordance with the Table of Disincentives as a result of appraisal where the relevant appraisal falls on or after the 1st day of April, 1988 – Alternative method.-

Subject to the provisions of sub-rules (2) and (4) of rule 9, if a Development Officer does not exceed the expense limit in three successive appraisal years, the current decrement/s pertaining to one year may be reinstated with effect from the relevant appraisal date next following the last such appraisal year.

- 11. Provident Fund.-** (1) Notwithstanding anything contained in rule 8 of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Terms and Conditions of Service) Rules, 1986, where the current decrements are reinstated to a Development Officer from the relevant appraisal date in accordance with the provisions contained in rule 9 or 10, the Corporation shall contribute to the Provident Fund established by it (hereinafter referred to as the "Fund") a maximum amount of 10 per cent

of the aggregate of the basic pay comprised in such decrements in relation to the period for which those decrements have been reinstated:

Provided that if during the period or part of the period in which the said decrements were in force, the rate at which the employer's contribution was higher than 10 per cent, the Corporation may contribute at such higher rate on that part of the basic pay pertaining to the relevant period:

Provided further that the Development Officer shall contribute to the Fund an amount equal to the contributions required of the Corporation as his additional contribution in accordance with the rules of the Fund and in such manner as he may be directed by the Corporation.

- (2) The Corporation shall credit its contributions to the Fund as and when and to the extent the Development Officer makes such additional contributions under the second proviso to sub-rule (1).
- (3) The contributions made by the Corporation under sub-rule (1) shall not be available for any purpose for which the employer's contributions are not available under the rules of the Fund.
- (4) Nothing contained in this rule shall apply to a Development Officer who is contributing to a superannuation fund approved by the Corporation.

12. Special Cases.- The Managing Director may, on the recommendation of the Zonal Manager, review any case of a Development Officer after the date of reduction in basic pay in pursuance of the Table of Disincentives if he does not qualify for reinstatement under rule 9 or rule 10 and grant such relief, having regard to the merits of the case, but not exceeding the relief that would have been admissible to him had he qualified himself under any of the said rules for reinstatement.

13. Incentives.- The Incentive Bonus may be allowed to a Development Officer for any preceding year under any Scheme approved by the Corporation from time to time.

14. Promotion of Development Officers.- Any Development Officer considered suitable may be promoted as Assistant Branch Manager or Assistant Administrative Officer, in accordance with rule 7 of the staff rules.

15. Re-appointment of terminated Development Officer.- If a Development Officer, whose services are terminated in pursuance of rule 7 has completed at least seven years of service in Class II on the date of such termination and has not completed 55 years of age, he shall be eligible for

reappointment in the service of the Corporation to do administrative work in Class III either as Assistant or Record Clerk in accordance with such qualification and suitability as may be specified under the Life Insurance Corporation of India (Reappointment of Terminated Development Officers) Rules, 1990:

Provided that notwithstanding the break in service as a consequence of termination, his service in the Corporation shall be deemed to be continuous for the purpose of leave; and also for the purpose of gratuity or provident fund if he has not received or if he has received but repays to the Corporation such amount of gratuity or provident fund as he has received.

16. Repeal and Savings.- (1) The Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989 are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, the appraisal year which has commenced prior to the date of publication of these rules, the provisions of the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989 shall apply for that appraisal year as if the said rules had not been repealed.

(3) Notwithstanding such repeal, any rules made, any thing done or any action taken under the Life Insurance Corporation of India Development Officers (Revision of Certain Terms and Conditions of Service) Rules, 1989 shall be deemed to have been made, done or taken under these rules.

(4) Nothing contained in these rules shall be deemed to affect the right of the Competent Authority to discharge, retire, or determine the service of a Development Officer in accordance with the Life Insurance Corporation of India (Staff) Rules, 1960 (hereinafter referred to as the Staff Rules) or to affect the right of the disciplinary authority to impose any penalty on him under rule 39 of the staff rules on any grounds specified therein or to apply the staff rules to Development Officers in respect of matters not dealt with in these rules.

17. Interpretation.- The Chairman may from time to time, issue such instructions as may be necessary to give effect to and carry out the provisions of the Rules. Where any doubt or difficulty arises as to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government for its decision.

[F. No. S-11012/02/2008-Ins. III]

TARUN BAJAJ, Jt. Secy.

